the Simla Agreement so as to create an atmosphere conducive to the interests of peace and good neighbourliness.

1984 के दंगों के तथा पंजाब और जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के शिकार लोगों को राहत प्रदान करना

2436. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :**
श्री शिव प्रताप मिश्र :
श्री महेन्द्र प्रसाद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1984 के दंगा-पीड़ितों को राहत देने हेतु क्या सरकार ने हाल ही में किसी योजना की घोषणा की है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ऐसी ही योजना को पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों की गतिविधियों से प्रभावित लोगों पर भी लागू करने का विचार रखती है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) दिल्ली में नवम्बर, 1984 के दंगा-पीड़ितों को राहत देने हेतु हाल ही में सरकार ने निम्नलिखित योजनाओं की घोषणा की है :

(1) विधवाओं को और 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को, जिनके आजीविका कमाने वाले या आजीविका कमाने वाले भावी सदस्य की मृत्यु हो गई हो उन्हें दी जाने वाली पेंशन की राशि 15.3.90 से 400/- रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000/- रुपये प्रतिमाह कर दी गई है ।

(2) जब तक विधवाओं का रोजगार करने योग्य लड़का लड़की कमाऊ सदस्य नहीं हो जाते हैं तब तक विधवाओं को पेंशन के अतिरिक्त 16-6-90 से 1000 रु. प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।

(3) रिहायशी इकाइयों की क्षति के लिए मुआवजा बढ़ा दिया गया है। आंशिक क्षति के लिए 2000/- रुपये भारी क्षति के लिए 10,000/- रु. और पूर्ण क्षति के लिए 20,000/- रुपये। पहले इस प्रकार के मुआवजा का दर आंशिक क्षति के लिए 1000/- रु. भारी क्षति के लिए 5000/- रुपये और पूर्ण क्षति के लिए 10,000/- रुपये था।

(4) वर्ष 1989-90 के शैक्षिक वर्ष से आगे स्कूल जाने वाले बच्चों को 50/- रु. और कालेज जाने वाले बच्चों को 100/- रुपये प्रतिमाह प्रति वजीफा दिया जाता है।

(ख) यह पंजाब और जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के क्षेत्र में आता है।

Demands of Autonomous State Demand Committee of Assam

2437. SHRI G. G. SWELL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Minister of State for Home Affairs visited the Karbi Anglong District of Assam in the month of June and assured the people and the leaders of the Autonomous State Demand Committee that a dialogue on their demand had started on the very day of his visit;

(b) whether there has been any follow-up action in the matter; and

(c) if so, the framework of the proposed dialogue?